that subject. But, Sir, if you desire, I would answer this question.

Mr. Speaker: Yes.

Shri Hathi: The officer-oriented scheme is an experiment which we are studying in the Works, Housing Ministry. Under that scheme we do away with some of the tiers through which the file passes before reaching an officer of the status of Deputy Secretary or Joint Secretary so that the time taken in disposing of cases may be decreased. If that scheme is implemented some of the Assistants will be rendered surplus. For the surplus staff we are having a common cell where they will be given suitable training and absorbed in other places. There will not be any retrenchment.

Shri Ranga: In view of the fact that this so-called economy drive as well as ban and non-recruiting of people unnecessarily, all these were as old as Pantji's Home Ministership —at that time also these things were doled out to us—how is it that all these years Government has not declared any definite policy of not replacing wastage so that it would be possible for them to economise, in view of the fact that there is wastage all these years and superfluous staff in one Ministry or the other?

Shri Hathi: As I said, we are not doing replacement in some cases so that over-staffing may not be there.

दिल्ली में विक्रय-कर में वृद्धि

\+

*151. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री ह० चं० सामन्त :
श्री बागड़ी :

श्री रामसेवक यादव :
श्री बड़े :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में विक्रय-कर में 5 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यह विक्रय-कर किन वस्तुओं पर बढ़ाया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) जून, 1963 से दिल्ली में विक्रयकर की दरों में कोई वृद्धि नहीं हुई । अतिरिक्त साधनों में वृद्धि करने तथा दिल्ली और उसके पड़ौसी राज्यों में कर की दरों में विषमता को कम करने की दृष्टि से वर्तमान दरों में कुछ परिवर्तन करने के कुछ सुझाव विचाराधीन हैं ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : मंत्री महोदय ने कहा है कि कुछ सुझाव विचाराधीन हैं । मैं जानना चाहता हूं कि इन पर कब तक अंतिम निर्णय हो जाएगा ?

श्री हाथी : अंतिम निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है । लेकिन बातचीत हो गई है । इसके बाद निर्णय लिया जाएगा ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या सरकार का ध्यान इस ओर गया है कि सरकार ने बिक्री कर तो बढ़ाया नहीं लेकिन बाजार में मूल्यों में वृद्धि हो गई है ? यदि हां तो इसको रोकने के लिए सरकार ने क्या किया है ?

श्री हाथी : वह तो दूसरा प्रश्न है । लेकिन बिक्री कर बढ़ाने की जो बात है, उसका एक कारण यह है कि पंजाब, राजस्थान,

उत्तर प्रदेश वगैरह में सेल्स-टैक्स ज्यादा परिमाण में है या कम है और किसी जगह नहीं भी है। परिणाम इसका यह होता है कि यहां का माल दूसरे राज्यों में जाता है और उन राज्यों की इकोनोमी में मुश्किलात पैदा होती है।

श्री बड़े : क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली आदि में इस टैक्स की दरों में बहुत विषमता है ? यदि हां तो यूनिफार्म रेट क्यों नहीं किया जाता है ? इससे सेल्स टैक्स का रेट एक हो जाएगा और भावों में विषमता नहीं रहेगी।

श्री हाथी : यही बात है। प्लानिंग कमिशन की एक मीटिंग बुलाई थी। उस में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आदि के लोग आए थे। मध्य प्रदेश के तो नहीं क्योंकि वह इस जोन में नहीं आता है, नार्दर्न जोन में नहीं आता है। उस में यह हुआ कि जहां सेल्स टैक्स नहीं है वहां तो लगाना ही होगा और जहां कम है वहां बढ़ाया जाए। अब यह जो बात है, उसी के बारे में यह प्रश्न है और इस बारे में विचार हो रहा है।

श्री म० ला० द्विवेदी : क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बात पर गौर किया है कि विभिन्न राज्यों में जो कर ज्यादा लगा हुआ है वहां इसको कम कर दिया जाए ताकि दिक्कतें न बढ़ें बजाय इसके कि बढ़ाने की बात आप सोचें ? क्या सरकार को यह भी पता है कि सेल्स टैक्स की चोरी होती है और वह इस तरह से कि लोग बगैर कैश मीमो के माल खरीद लेते हैं जिससे सरकार को नुक्सान भी होता है और दूसरे माल की बिक्री करने वाले जो सौदागर होते हैं उन पर भी इसका असर पड़ता है ?

श्री हाथी : कर कम किया जाए या नहीं वह बात तो प्लानिंग कमीशन ने नहीं सोची है। प्लानिंग कमीशन तो दर बढ़ाना चाहता है। इसलिए कर बढ़ाने की बात कर रहे हैं।

श्री म० ला० द्विवेदी : सेल्स टैक्स की जो चोरी होती है, उसका जवाब नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय : आप कहते हैं कि नीचे जो है उसको हटा दिया जाए।

श्री म० ला० द्विवेदी : हटा दिया जाए तभी तो सेल्स टैक्स की चोरी घटेगी। मैंने यह जानना चाहा कि इस चोरी को रोकने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

श्री बागड़ी : किसी प्रांत में दर कम है किसी में ज्यादा है और किसी में यह कर ही नहीं है। जहां नहीं है वहां आप लगाने की सोच रहे हैं और जहां कम है उसको बढ़ाने की बात सोच रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस का एक बाहिद इलाज यह है कि बिक्री कर वहां लगा दिया जाए जहां उत्पादन होता है और एक ही दर से लगा दिया जाए और अलग अलग जगहों पर से रिटेल में जो लगता है, उसको हटा दिया जाए। ऐसा करने से समानता भी आ जाएगी, कभी बेशी भी नहीं रह जाएगी और चोरी की सम्भावना भी नहीं रह जाएगी। क्या सरकार के यह सुझाव विचाराधीन हैं और अगर है तो वह इस सम्बन्ध में क्या कर रही है ?

श्री हाथी : वह तो अलग बात है। बिक्री कर और एक्साइज ड्यूटी अलग चीजें हैं। एक्साइज ड्यूटी डालने का अलग प्रश्न है।

Shri S. C. Samanta: May I know whether there is any proposal to amalgamate sales tax with excise duty or production tax in Delhi?

Shri Hathi: No; there is no proposal as yet.

श्री रामसेवक यादव : मैं जानना चाहता हूं कि क्या बिक्री कर को जीवन की जो उपयोगी वस्तुयें हैं, जो बहुत आवश्यक वस्तुयें हैं, उन पर से हटाने का भी विचार हो रहा है ? साथ ही मैं यह जानना चाहता हूं कि बिक्रीकर का खास तौर से और ज्यादा तर खरीद

वालों के ऊपर बोझ पड़ता है, इस वास्ते क्या इस के नाम को भी बदलने की कोशिश होगी, इसको बिक्री कर न कह कर खरीद कर कहा जाएगा ?

श्री हाथी । इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि जब बिक्री कर बढ़ाया जाए तो ज्यादा तर लग्जरी गुड्ज पर बढ़ाया जाए ।

Dr. L. M. Singhvi: In view of the large-scale evasion and the prevalence of disproportionate disparities in the incidence of sales-tax in several States, may I know whether the Government have proposed or have effected any machinery for consultation among the States concerned so that the disproportion and disparities may be warded off?

Shri Hathi: In fact, the Planning Commission did have a meeting of the representatives of the various States and it was after consultation that it was decided that there should be some sort of uniformity between all the States. But the difficulty arose because Delhi has, on several items, no sales-tax whatsoever whereas other States have 7 per cent, 8 per cent, like that; therefore, people from neighbouring States come here, take away the goods as consumers and do not pay tax either here or there; hence this difficulty. It was exactly the result of consultation with the various States that this decision to have a uniform rate of tax was arrived at.

Industries in Border Areas

\+

*152. **Shri Narayan Reddy:**
Shri Lahtan Chaudhry:
Shri Subodh Hansda:
Shri S. C. Samanta:
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shri M. L. Dwivedi:
Shri P. C. Borooah:
Shri P. R. Chakraverti:
Shri K. N. Tiwary:
Shri Himatsingka:
Shri Rameshwar Tantia:
Shri Onkar Lal Berwa:
Shri Daji:
Shri Madhu Limaye:
Shri Vishwa Nath Pandey:
Shri Indrajit Gupta:
Dr. L. M. Singhvi:
Shri Bade:
Shri Bagri:
Dr. Ram Manohar Lohia:
Shri Kishen Pattnayak:
Shri Ram Sewak Yadav:
Shri Yashpal Singh:
Shri Gulshan:
Shrimati Savitri Nigam:
Shri Vishram Prasad:
Shri Utiya:
Shri A. N. Vidyalankar:
Shri Bibhuti Mishra:
Shri Hem Barua:
Shri R. S. Pandey:
Shri Mohan Swarup:
Shri Basumatari:
Shri Sidheshwar Prasad:

Will the Minister of **Labour, Employment and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have under consideration any proposal to help industries and workers in the border areas;

(b) if so, the main features thereof;

(c) whether it is also a fact that an inter-Ministerial Committee set up by the Labour Ministry in pursuance of the recommendations of the Indian Labour Conference has recently met and considered the unemployment resulting from the bombing of factories by Pakistan planes;

(d) if so, the subjects discussed thereat; and

(e) the outcome thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan): (a) and (b). A statement (No. 1). showing the steps taken by the Central Government and the State Governments to help industries and workers in border areas is laid on the Table of the House . [*Placed in Library. See* No. LT-5539 (1)/66].

(c) Yes. The first meeting of the inter-Ministerial Committee was held on the 23rd December, 1965.